



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004/8 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4; 27 फरवरी, 2004

संख्या वि० स०-लैज-अ. बजट/1-10-2004.—हिमाचल प्रदेश विधान की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (2004 का

विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 27 फरवरी, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे 0 आर 0 गाजटा,
सचिव,
हि 0 प्र 0 विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2004 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग 25,49,45,69,000 रुपए (पच्चीस अरब, उन्चास करोड़, पैतालीस लाख, उन्हत्तर हजार रुपए) है, वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अप्रैल से जुलाई मास की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित संदायों के विभिन्न प्रभारों का चुकाने के लिए निकाली जाए ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए 25,49,45,69,000 रुपए की राशि निकालना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का विनियोग, अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनुधिक		
भाग महत्वा	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपए	रुपए	रुपए
1	विधान सभा (राजस्व)	2,04,32,000	5,72,000	2,10,04,000
	(पूजी)	59,34,000	—	59,34,000
2	राज्यपाल और मंत्रि-परिषद् (राजस्व)	1,44,77,000	49,09,000	1,93,86,000
	(पूजी)	—	—	—
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	9,53,45,000	2,37,06,000	11,90,51,000
	(पूजी)	90,00,000	—	90,00,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	15,25,96,000	70,72,000	15,96,68,000
	(पूजी)	1,67,000	—	1,67,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	47,94,96,000	—	47,94,96,000
	(पूजी)	23,000	—	23,000
6	आवकारी और कराधान (राजस्व)	5,17,43,000	—	5,17,43,000
	(पूजी)	—	—	—
7	पुलिस और मम्बद (राजस्व)	61,15,77,000	—	61,15,77,000
	(पूजी)	1,43,91,000	—	1,43,91,000
8	शिक्षा (राजस्व)	3,03,03,88,000	—	3,03,03,88,000
	(पूजी)	10,45,67,000	—	10,45,67,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	1,22,57,82,000	1,27,000	1,22,59,09,000
	(पूजी)	16,94,00,000	—	16,94,00,000
10	लोक निर्माण— (राजस्व)	42,77,96,000	—	42,77,96,000
	(पूजी)	2,19,23,000	—	2,19,23,000
11	कृषि (राजस्व)	23,92,37,000	—	23,92,37,000
	(पूजी)	12,74,34,000	—	12,74,34,000
12	उद्योग (राजस्व)	16,09,52,000	—	16,09,52,000
	(पूजी)	2,58,13,000	—	2,58,13,000
13	मिर्बाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	21,23,02,000	—	21,23,02,000
	(पूजी)	37,43,68,000	3,34,000	37,47,02,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व)	22,48,10,000	—	22,48,10,000
	(पूजी)	62,30,000	—	62,30,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व)	28,45,99,000	—	28,45,99,000
	(पूजी)	5,16,94,000	—	5,16,94,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	50,10,80,000	—	50,10,80,000
	(पूजी)	48,26,000	—	48,26,000

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
17	सड़क और पुल (राजस्व)	1,03,69,64,000	—	1,03,69,64,000
	(पूँजी)	66,92,28,000	1,00,00,000	67,92,28,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व)	7,38,23,000	1,000	7,38,24,000
	(पूँजी)	1,55,27,000	—	1,55,27,000
19	सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता (राजस्व)	37,81,81,000	—	37,81,81,000
	(पूँजी)	1,47,33,000	—	1,47,33,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	28,55,56,000	—	28,55,56,000
	(पूँजी)	37,27,000	—	37,27,000
21	सहकारिता (राजस्व)	3,95,45,000	—	3,95,45,000
	(पूँजी)	2,31,38,000	—	2,31,38,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	3,78,10,000	—	3,78,10,000
	(पूँजी)	17,79,000	—	17,79,000
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	20,54,19,000	—	20,54,19,000
	(पूँजी)	31,32,67,000	—	31,32,67,000
24	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व)	2,99,14,000	—	2,99,14,000
	(पूँजी)	17,000	—	17,000
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	10,18,96,000	—	10,18,96,000
	(पूँजी)	5,76,97,000	—	5,76,97,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)	1,13,67,000	—	1,13,67,000
	(पूँजी)	36,67,000	—	36,67,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	7,24,14,000	—	7,24,14,000
	(पूँजी)	60,00,000	67,000	60,67,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास (राजस्व)	79,71,17,000	—	79,71,17,000
	(पूँजी)	46,10,65,000	—	46,10,65,000
	वित्त (राजस्व)	2,01,97,20,000	6,25,24,81,000	8,27,22,01,000
	(पूँजी)	3,80,00,000	2,96,64,70,000	3,00,44,70,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	4,67,80,000	—	4,67,80,000
	(पूँजी)	49,67,000	—	49,67,000
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	63,66,38,000	37,88,000	64,04,26,000
	(पूँजी)	19,07,04,000	—	19,07,04,000
	कुल जोड़	16,22,50,42,000	9,26,95,27,000	25,49,45,69,000
	(राजस्व)	18,50,57,56,000	6,29,26,56,000	19,79,84,12,000
	(पूँजी)	2,71,92,86,000	2,97,68,71,000	5,69,61,57,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 और 204 के अधीन विहित प्रक्रिया के पूर्ण होने तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अप्रैल से जुलाई माह के लिए अपेक्षित धन के ऐसे व्यय को जो संचित निधि पर प्रभारित है और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्यय को पूरा करने के लिए निकालने का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है। मांगे गये धन में वर्ष 2004-2005 की वस्तुतः नई स्कीमों का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

नियमित बजट विधान सभा द्वारा जुलाई, 2004 में पारित किया जाना है। अतः अप्रैल से जुलाई, 2004 के लिए लेखा अनुदान अभिप्राप्त किया जा रहा है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

दिनांक : 27 फरवरी, 2004.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल संख्या वित्त-ए-सी (1)-1/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करने हैं।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2004

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

दीरमन्न सिंह,
मुख्य मन्त्री।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि)।

शिमला :

दिनांक : 27 फरवरी, 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2004

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 2004-2005.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2004.

Withdrawal
of Rs. 25,
49,45,69,000
from and
out of the
Consolida-
ted Fund
of the
State of
Himachal
Pradesh for
the financial
year
2004-2005.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 25,49,45,69,000 (Rupees Twenty five hundred and forty nine crores, forty five lakhs and sixty nine thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the months of April to July of the financial year 2004-2005 in respect of the services specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Demand No.	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue)	2,04,32,000	5,72,000	2,10,04,000
	(Capital)	59,34,000	—	59,34,000
2	Governor and (Revenue)	1,44,77,000	49,09,000	1,93,86,000
	Council of Ministers (Capital)	—	—	—
2	Administration of (Revenue)	9,53,45,000	2,37,06,000	11,90,51,000
	Justice and Election (Capital)	90,00,000	—	90,00,000
4	General Adminis- (Revenue)	15,25,96,000	70,72,000	15,96,68,000
	tration (Capital)	1,67,000	—	1,67,000
5	Land Revenue (Revenue)	47,94,96,000	—	47,94,96,000
	and District Adminis- (Capital)	23,000	—	23,000
6	Excise and Taxation (Revenue)	5,17,43,000	—	5,17,43,000
	(Capital)	—	—	—
7	Police and Allied (Revenue)	61,15,77,000	—	61,15,77,000
	Organisations (Capital)	1,43,91,000	—	1,43,91,000
8	Education (Revenue)	3,03,03,88,000	—	3,03,03,88,000
	(Capital)	10,45,67,000	—	10,45,67,000
9	Health and Family (Revenue)	1,22,57,82,000	1,27,000	1,22,59,09,000
	Welfare (Capital)	16,94,00,000	—	16,94,00,000
10	Public Works— (Revenue)	42,77,96,000	—	42,77,96,000
	Buildings (Capital)	2,19,23,000	—	2,19,23,000
11	Agriculture (Revenue)	23,92,37,000	—	23,92,37,000
	(Capital)	12,74,34,000	—	12,74,34,000
12	Horticulture (Revenue)	16,09,52,000	—	16,09,52,000
	(Capital)	2,58,13,000	—	2,58,13,000
13	Irrigation and Flood (Revenue)	21,23,02,000	—	21,23,02,000
	Control (Capital)	37,43,68,000	3,34,000	37,47,02,000
14	Animal Husbandry, (Revenue)	22,48,10,000	—	22,48,10,000
	Dairy Development (Capital)	62,30,000	—	62,30,000
15	Planning and Back- (Revenue)	28,45,99,000	—	28,45,99,000
	ward Area Sub-Plan (Capital)	5,16,94,000	—	5,16,94,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)	50,10,80,000	—	50,10,80,000
	(Capital)	48,26,000	—	48,26,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	1,03,69,64,000	—	1,03,69,64,000
	(Capital)	66,92,28,000	1,00,00,000	67,92,28,000
18	Supplies, Industries (Revenue)	7,38,23,000	1,000	7,38,24,000
	and Minerals (Capital)	1,55,27,000	—	1,55,27,000
19	Social Justice and (Revenue)	37,81,81,000	—	37,81,81,000
	Empowerment (Capital)	1,47,33,000	—	1,47,33,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development (Revenue)	28,55,56,000	—	28,55,56,000
	(Capital)	37,27,000	—	37,27,000
21	Co-operation (Revenue)	3,95,45,000	—	3,95,45,000
	(Capital)	2,31,38,000	—	2,31,38,000
22	Food and Warehousing (Revenue)	3,78,10,000	—	3,78,10,000
	(Capital)	17,79,000	—	17,79,000
23	Water and Power Development (Revenue)	20,54,19,000	—	20,54,19,000
	(Capital)	31,32,67,000	—	31,32,67,000
24	Printing and Stationery (Revenue)	2,99,14,000	—	2,99,14,000
	(Capital)	17,000	—	17,000
25	Road and Water Transport (Revenue)	10,18,96,000	—	10,18,96,000
	(Capital)	5,76,97,000	—	5,76,97,000
26	Tourism and Civil Aviation (Revenue)	1,13,67,000	—	1,13,67,000
	(Capital)	36,67,000	—	36,67,000
27	Labour Employment And Training (Revenue)	7,24,14,000	—	7,24,14,000
	(Capital)	60,00,000	67,000	60,67,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development (Revenue)	79,71,17,000	—	79,71,17,000
	(Capital)	46,10,65,000	—	46,10,65,000
29	Finance (Revenue)	2,01,97,20,000	6,25,24,81,000	8,27,22,01,000
	(Capital)	3,80,00,000	2,96,64,70,000	3,00,44,70,000
30	Miscellaneous (Revenue)	4,67,80,000	—	4,67,80,000
	(Capital)	49,67,000	—	49,67,000
31	General Services (Revenue)	63,66,38,000	37,88,000	64,04,26,000
	(Capital)	19,07,04,000	—	19,07,04,000
	Grand Total	16,22,50,42,000	9,26,95,27,000	25,49,45,69,000
	(Revenue)	13,50,57,56,000	6,29,26,56,000	19,79,84,12,000
	(Capital)	2,71,92,86,000	2,97,68,71,000	5,69,61,57,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the months of April to July, 2004 of the Financial year 2004-2005 pending the completion of the procedure prescribed in Articles 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 2004-2005.

Regular Budget is to be passed by the Legislative Assembly in July, 2004. As such the vote on account is being obtained for April to July, 2004.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
the 27th February, 2004.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A. C. (1)-1/2004]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 2004, recommends, under Article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT)
BILL, 2004

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 2004-2005.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. [L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
the 27th. February., 2004.